RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 24 JULY TO 30 JULY 2019 प्रति बुधवार वर्ष 04 अंक 48 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन, सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने का सुझाव

Page 2

पानी की प्लास्टिक बोतलों से रेलवे बना रही टी-शर्ट

Page 5

मॉनसून की सुस्त चाल से सोयाबीन रकबे में 10 प्रतिशत गिरावट का अनुमान

Page 7

editoria!

कामयाबी का चांद

अंतरिक्ष में भारत ने सफलता की एक और लंबी छलांग लगाई है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी 'इसरो' ने सोमवार को चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक संपन्न की। इससे पहले चंद्रयान-2 को 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर एक तकनीकी गड़बड़ी पकड़ में आ जाने से लॉन्चिंग टाल दी गई थी। इसकी सफलता ने जाहिर किया है कि अब क्रायोजेनिक इंजन पर हमारी पकड़ मजबूत हो गई है। चंद्रयान-1 की खोजों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान-2 को भेजा गया है। चंद्रयान-1 द्वारा खोजे गए पानी के अणुओं के साक्ष्य के बाद चांद की सतह पर, उसके नीचे और अति विरल वातावरण में पानी के अणुओं के वितरण का अध्ययन करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। चंद्रयान-2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। चंद्रमा का यह ऐसा इलाका है, जिसकी अब तक सीधे कोई जांच नहीं हुई है। मून मिशनों के माहिर अमेरिका, रूस और चीन ने भी अभी तक इस तरफ कोई लैंडिंग नहीं की है। इस इलाके के कुछ क्रेटर हमेशा छाया में रहते हैं और सूरज की किरणें न पड़ने से यहां बर्फ की शक्ल में पानी मिलने की संभावना ज्यादा है। हाल में कुछ ऑर्बिट मिशंस ने भी इस पर मोहर लगाई है। कहा जा रहा है कि बेहद ठंडे क्रेटर्स में सौर परिवार की प्रारंभिक सामग्री के अवशेष भी मौजूद हो सकते हैं है। पानी की मौजूदगी आगे चलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इंसान की लंबी, सशरीर उपस्थिति के लिए केंद्रीय भूमिका निभा सकती है। यहां की सतह की जांच चंद्रमा के निर्माण को और गहराई से समझने में मददगार साबित होगी। भविष्य के मिशनों के लिए संसाधन की दृष्टि से इसके इस्तेमाल की संभावनाओं का पता लगाना संसार के सभी चंद्र अभियानों का एक बड़ा उद्देश्य है ही। सबसे बड़ी बात यह कि पृथ्वी के इस एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह को दुर्लभ अंतरिक्षीय सूचनाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। हीलियम-3 जैसा बहुमूल्य खनिज मिलने की भी आशा है, जिसके एक टन की कीमत करीब 5 अरब डॉलर हो सकती है। चंद्रमा से ढाई लाख टन हीलियम-3 लाया जा सकता है, जिसकी कीमत कई लाख करोड़ डॉलर होगी। इस काम के लिए चीन ने भी इसी साल अपना चांग ई-4 यान भेजा था। अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ की चंद्रमा के प्रति दिलचस्पी बढ़ने की यह एक बड़ी वजह है। दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के मालिक जेफ बेजोस का इरादा चंद्रमा पर कॉलोनी बसाने का है। इस सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिक निश्चय ही बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इसके लिए जीतोड़ परिश्रम किया और शुरुआती नाकामियों के बावजूद अपना धैर्य बनाए रखा। यह एक दूरगामी अभियान है, जिसमें सफलता-असफलता के दौर आते-जाते रहेंगे। हमें हर स्थिति में अपने वैज्ञानिकों के साथ खड़ा होना होगा और अपनी अपेक्षाओं का बोझा लादकर उन पर अतिरिक्त दबाव बनाने से बचना होगा।

खाड़ी में तनाव का असर

कच्चे तेल में दो फीसद की उछाल

पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका

नई दिल्ली। एजेंसी

खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोमवार को कच्चे तेल के दाम में दो फीसदी से ज्यादा का उछाल आया। ईरान द्वारा ब्रिटिश टैंकर को जब्त किए जाने की घटना के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में तेजी का सिलसिला लगतार तीसरे दिन जारी रहा। हालांकि घरेलू तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। कच्चा तेल सोमवार को 63.69 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। हालांकि दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में सोमवार को पेट्रोल के दाम पूर्ववत क्रमशः 73.35 रुपये, 75.77 रुपये, 78.96 रुपये और 76.18 रुपये प्रति लीटर बने रहे। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी पूर्ववत क्रमशः 66.24 रुपये, 68.31 रुपये और 69.43 रुपये और 69.96 रुपये प्रति लीटर बने हुए हैं। डीजल के दाम में लगातार 10 दिनों से स्थिरता बनी हुई और पेट्रोल में लगातार चौथे दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई तेजी से भारतीय वायदा बाजार में भी कच्चे तेल के भाव में तकरीबन 2.5 फीसदी का उछाल आया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर कच्चे तेल के अगस्त वायदा अनुबंध में अपराह्न 15.35 बजे 93 रुपये यानी 2.43 फीसदी की तेजी के साथ 3,921 रुपये प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था जबकि इससे पहले भाव 3,943 रुपये प्रति बैरल तक उछला। उधर, अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकॉनटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर ब्रेंट क्रूड के सितंबर वायदा अनुबंध में 2.11 फीसदी की तेजी के साथ 63.79 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था जबकि इससे पहले ब्रेंट क्रूड का भाव 64.02 डॉलर प्रति बैरल तक उछला। वहीं, न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के अगस्त डिलीवरी अनुबंध में 1.78 फीसदी की तेजी के साथ 56.62 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था जबकि इससे पहले डब्ल्यूटीआई का भाव 57.02 डॉलर प्रति बैरल तक उछला।

कच्चे तेल वायदा भाव में तेजी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख के बीच सटोरियों के सौदा बढ़ाये जाने से वायदा बाजार में कच्चे तेल की कीमत बुधवार को 0.59 प्रतिशत बढ़कर 3,939 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गयी। विश्लेषकों के अनुसार प्रतिभागियों के सौदा बढ़ाने से कच्चे तेल के भाव में तेजी आयी।मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जुलाई महीने की डिलिवरी के लिये कच्चा तेल 23 रुपये यानी 0.59 प्रतिशत बढ़कर 3,939 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गयी। इसमें 17,895 लॉट के लिये कारोबार हुआ।इस बीच, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 0.39 प्रतिशत बढ़कर 56.99 डालर पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.20 प्रतिशत बढ़कर 63.96 डालर बैरल पर पहुंच गयी।

25 जुलाई को होगी जीएसटी परिषद की बैठक

ई-व्हीकल पर कम हो सकता है टैक्स

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 36वीं बैठक 25 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार य बैठक दोपहर तीन बजे के बाद होगी। हालांकि बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी दी गयी है लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि परिषद की पिछली बैठक में कुछ मामलों को मंत्रियों की समितियों को सौंपे गये थे जिन पर इस बैठक में निर्णय लिये जाने की संभावना है। इसके साथ ही फिटमेंट समिति को भी कुछ मामले सौंपे गये थे और उन पर 36वीं बैठक में विचार किये जाने की संभावना है।

ई-वाहनों पर टैक्स कटौती संभव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वाली जीएसटी परिषद की 25 जुलाई को बैठक होगी। इस बैठक में ई-वाहनों पर कर में कमी के प्रस्ताव पर निर्णय किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि परिषद की 36वीं बैठक में सौर ऊर्जा उत्पादक प्रणालियों एवं विंड टर्बाइन परियोजनाओं पर जीएसटी लगाए जाने के बाबत उनमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यांकन के विषय में भी फैसला किया जाएगा। ई-वाहनों को बढ़ावा देने को केंद्र ने जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सिफारिश की है।

21 जून को हुई थी पिछली मीटिंग

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद परिषद की पहली बैठक 21 जून को हुई थी। यह परिषद की 35वीं बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जीएसटी परिषद की बैठक में पहली बार भाग लिया था। इसमें कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई थी लेकिन 5 जुलाई को बजट पेश होने के कारण कोई घोषणा नहीं की गई।

प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन

सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने का सुझाव

नई दिल्ली। एजेंसी

एक हाई-लेवल कमेटी ने देश में डिजिटल करेंसी के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की सिफारिश की है। उसने अपनी सिफारिश में बैन का उल्लंघन होने पर 10 साल तक कैद की सजा और 25 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाने का सुझाव दिया है। अगर सरकार कमेटी की सिफारिशें मान लेती है तो डिजिटल करेंसी सेगमेंट में उतरने की इच्छुक फेसबुक जैसी दिग्गजों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। इससे आरबीआई के नियमों से बचते हुए पीयर टू पीयर ट्रेडिंग के जरिए देश में चलाए जा रहे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को भी बड़ा नुकसान होगा। कमेटी यह भी चाहती है कि सरकार और देश में ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की संभावनाओं पर गौर करें।

डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 2 नवंबर 2017 को गठित उच्चस्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कमेटी चाहती है कि सरकार की तरफ से जारी क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर बाकी सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर इंडिया में पाबंदी लगाई जाए।' कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्रिप्टोकरेंसी पर हमलावर रही है क्योंकि ये फॉरेन की प्राइवेट कंपनियों की तरफ से जारी होती हैं। उसने इस ट्रेड से जुड़ी सभी एंटिटीज (एक्सचेंजों, इंडिविजुअल, ट्रेडर्स और दूसरी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज सहित) पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग की है। उसने ऐसी करेंसी में होने वाली डीलिंग को आपराधिक कृत्य करार दिए जाने का प्रस्ताव दिया है।

कमेटी ने जिस मसौदा कानून का प्रस्ताव दिया है, उसके मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी के प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयोग पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उसने दोषियों के खिलाफ एक से 10 साल तक कैद की सजा और जुर्माना लगाए जाने का सुझाव दिया है। कमेटी ने अपराध दूसरी बार होने की सूरत में जुर्माने के साथ 5 से 10 साल तक कैद की सजा का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की है। क्रिप्टोकरेंसी में डील करने वाले शख्स के चलते होने वाले लॉस या उसे हुए फायदे का तीन गुना या 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का सुझाव दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर को सौंपे जाने के बाद सार्वजनिक की गई हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट में इंडिया में क्रिप्टोकरेंसी को माइन, जेनरेट, होल्ड, सेल, डील, इश्यू, ट्रांसफर, डिस्पोज या यूज करने पर रोक के लिए कानून बनाए जाने का सुझाव दिया गया है। हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, 'देश में ऑफिशियल डिजिटल करेंसी पेश किए जाने पर खुले दिमाग से विचार किए जाने की सलाह दी जाती है।' रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई एक्ट में मौजूदा प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सकता है. जिसमें केंद्र सरकार को आरबीआई की तरफ से प्रस्तावित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बैंक नोट के तौर पर मंजूरी देने की इजाजत है। इससे वह इंडिया में लीगल टेंडर हो जाएगा।

IMF ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाया, चीन से आगे

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने 2019 और 2020 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटा दिया है। आईएमएफ ने दोनों वर्षों के लिए वृद्धि दर के अनुमान में 0.3-0.3 प्रतिशत की कटौती की है। यह घरेलू मांग के उम्मीद से कम होने को दिखाता है। आईएमएफ के ताजा अनुमान के अनुसार 2019 में भारत की वृद्धि दर सात प्रतिशत और 2020 में 7.2 प्रतिशत रहेगी। वॉशिंगटन के वित्तीय संस्थान ने हालांकि कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा और यह चीन से काफी आगे होगा। आईएमएफ ने कहा कि उसने दोनों वर्षों के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान में 0.3-0.3 प्रतिशत की कटौती की है।

आईएमएफ ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य 'अपडेट' में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019 में सात प्रतिशत रहेगी और 2020 में कुछ बढ़कर 7.2 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। इसकी वजह उम्मीद से कमजोर घरेलू मांग में कमी है। आईएमएफ ने कहा कि चीन में शुल्क वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव और कमजोर बाहरी मांग से पहले से संरचनात्मक सुस्ती झेल रही अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा। कर्ज पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए चीन को नियामकीय मजबूती की जरूरत होगी।

आईएमएफ ने कहा कि नीतिगत समर्थन की वजह से चीन की वृद्धि दर 2019 में 6.2 प्रतिशत और 2020 में 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। चिली की राजधानी सान्तियागो में रिपोर्ट जारी करते हुए आईएमएफ की भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि 2019 के लिए वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 3.2 प्रतिशत किया गया है। 2020 के लिए इसे घटाकर 3.5 प्रतिशत किया जा रहा है। गोपीनाथ ने कहा कि यह अप्रैल के हमारे अनुमान से दोनों वर्षों के लिए 0.1 प्रतिशत की कटौती है।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने लगाई पांच पायदान की छलांग

52वें स्थान पर पहुंचा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2019 में भारत पांच पायदान ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में पिछले साल भारत का स्थान 57वां था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को वैश्विक नवप्रवर्तन सूचकांक (GII) की रैंकिंग जारी की। जीआईआई रैंकिंग वार्षिक आधार पर कॉरनेल विश्वविद्यालय इनसीड, संयुक्त राष्ट्र विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) और जीआईआई नॉलेज पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित की जाती है।

जीआईआई ने इसके 12वें संस्करण में 80 संकेतकों के आधार पर 129 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग दी है। इन संकेतकों में बौद्धिक संपदा के लिए आवेदन जमा कराने की दर से लेकर मोबाइल ऐप का सृजन, शिक्षा पर खर्च और वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकाशन आते हैं। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर कायम है। सूचकांक में शामिल शीर्ष दस देश..... स्वीडन, अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी और इजरायल हैं।

पहले से ही इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि रैंकिंग में सुधार होगा। 2017 में भारत 60वें, 2016 में 66वें और 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। भारत का लक्ष्य इसमें पहली 25 अर्थव्यवस्थाओं में आने का है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस साल ब्रिटेन को पछाड़ते हुए दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसके अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

- **ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2019 में भारत पांच पायदान ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर पहुंच गया है**
- **जीआईआई ने इसके 12वें संस्करण में 80 संकेतकों के आधार पर 129 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग दी है**
- **2017 में भारत 60वें, 2016 में 66वें और 2015 में भारत 81वें स्थान पर था**
- **भारत का लक्ष्य इसमें पहली 25 अर्थव्यवस्थाओं में आने का है**

पावरफुल वीडियो कोलेबरेशन के एडवांस चरण में अवाया का प्रवेश

लॉन्च किया CU360, कॉम्पैक्ट एंड्रॉइड आधारित कोलेबरेशन यूनिट और AEMO

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कम्युनिकेशन तथा कोलेबरेशन को सहज और उन्नत बनाने के लिए समाधान प्रस्तुत करने के क्षेत्र में विश्व भर में अग्रणी कम्पनी, अवाया ने एक खास समाधान प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत भारत में क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अवाया ई कोलेबरेशन यूनिट ण्ळ360 तथा अवाया इक्विनॉक्स मीटिंग्स ऑनलाइन (एईएमओ) को प्रस्तुत किया गया। ण्ळ360 फुल एचडी 1080 ज का परफॉर्मेंस देने वाली एक कॉम्पैक्ट कोलेबरेशन यूनिट है जो किसी भी जगह को एक वीडियो कोलेबरेशन रूम में बदल कर वर्कप्लेस/ काम करने की जगह के अनुभव को पूरी तरह बदल देने का वादा करती है।

एक बंडलयुक्त सेवा के रूप में पेश की गई इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक 'अवाया इक्विनॉक्स मीटिंग्स ऑनलाइन' का प्रयोग पहले तीन महीनों के लिए निःशुल्क कर सकते हैं, इसके पश्चात् भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग किफायती शुल्क यानी मात्र 10 पैसे प्रति मिनिट की दर से किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में हडल रूम कोलेबरेशन तथा मीटिंग्स स्पेस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए पूरी तरह उत्पादकता से भरपूर, रचनात्मक माहौल बनाने के लिए प्रयासरत हैं ताकि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर साथ मिलकर आपसी बातचीत से भरपूर कॉन्फ्रेंस और चर्चा के लिए एकजुट हो सकें। इसके साथ ही, संस्थान रिमोट वर्कर्स (दूर रहकर काम करने वाले कर्मचारी) की संख्या में बढ़ोत्तरी को देखते हुए इस बात को समझ रहे हैं कि दुनियाभर में उनके संस्थान के लिए काम कर रहे अलग-अलग स्थानों के कर्मचारियों के साथ इनोवेटिव तकनीकी साधनों के जरिये जुड़ना आज की आवश्यकता बन गई है। ऐसे में अवाया की नई सुविधाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है।

अवाया IX CU360 ने काम करने की जगह के प्रचलित प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस के लिए निरंतर सहयोग देने के साथ टीमों के लिए स्मार्ट कोलेबरेशन प्रस्तुत करते हुए, पारम्परिक हडल रूम सैट अप्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसके एडवांस्ड फीचर्स जैसे फुल एचडी 1080ज वीडियो, एक 4के कैमरा सेंसर, 4के डिस्प्ले और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आदि शानदार यूज़र एक्सपीरियंस प्रस्तुत करते हैं। ड्युअल एचडी लाइव वीडियो कंटेंट सहित किसी भी स्टैंडर्ड बेस्ड वीडियो सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी तथा अवाया के यूसी सॉल्यूशंस के साथ इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएँ देने वाला, ण्ळ360 किसी भी आकार के व्यवसाय के लिए एंटरप्राइज क्लास फीचर्स प्रदान करता है। इन तमाम सुविधाओं के साथ ग्राहकों तथा कर्मचारियों के लिए इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन एक्सपीरिएंस प्रदान कर एक नई इबारत लिखने वाला ण्ळ360, किसी भी मीटिंग रूम या हडल स्पेस को और भी आकर्षक सुझाव उपलब्ध कराता है।

इस डिवाइस की लॉन्चिंग के दौरान अधिक जानकारी देते हुए श्री विशाल अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर, भारत तथा SAARC, ने कहा-'अवाया ने हमेशा से कार्यक्षमता और योग्यता के क्षेत्र में नए बेंचमार्क स्थापित करने तथा लोगों को और अच्छा अनुभव देने के लिए प्रयास किया है. अवाया ई कोलेबरेशन यूनिट CU360, जो कि एक शक्तिशाली वीडियो कोलेबरेशन पेशकश है, यह इंटेलिजेंट/बुद्धिमतापूर्ण हडल रूम सैट अप्स तथा क्लाउड बेस्ड वर्कस्पेस अनुभव प्रदान करते हुए अवाया के समाधान प्रस्तुतिकरण को और भी मजबूती देता है। इस यूनिट के साथ अवाया इक्विनॉक्स मीटिंग्स ऑनलाइन, का एकीकरण और भी आकर्षक प्रपोजिशन के तौर पर सामने आता है जो टीमों को यूज़र फ्रेंडली और उत्पादकतापूर्ण कोलेब्रेशन क्षमताएं उपलब्ध कराता है।' CU360 यूटिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और सिक्योरिटी के कई पहलुओं को मिलाकर, व्यक्तिगत कनेक्शन के साथ प्रशिक्षण, विचार-मंथन, टीम और ग्राहक मीटिंग के लिए एक विशेष अनुभव प्रदान करता है। कोलैबोरेशन यूनिट क्लाउड-आधारित एंड्रॉइड एप्लिकेशन तक पहुंच और उन्हें चला सकती है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी पसंद के क्लाउड-आधारित सहयोग टूल का उपयोग कर सकते हैं। इसे मोबाइल ऐप द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, साथ ही यह भविष्य की साझेदारियों के अनुरूप है।

OSIYA
DISTRIBUTOR LLP
A POLYMER HOUSE
DEALS IN ALL TYPE OF VIRGIN MATERIAL
Contact : Amit Midda 9109195544

Indore Depo :
206, Johari Palace,
51, MG Road, Indore 452001 (M.P.)
E : osiya.distributor@gmail.com

Raipur Depo :
D-432/5, Taigor Nagar, Raipur (C.G.)
E : osiya.distributor@gmail.com

ओपीएएल OPAL
ONGC एमआरपीएल MRPL
गेल GAIL
इंडियनऑयल IndianOil
HALDIA PETROCHEMICALS LTD
HMEL

लोकसभा में पास हुआ मोटर वाहन संशोधन विधेयक

गलत ड्राइविंग पर पहले से 30 गुना तक फाइन

नई दिल्ली। एजेंसी

लोकसभा ने मोटर वाहन (संशोधन) बिल-2019 को मंजूरी दे दी। इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं। तमाम मामलों में ड्राइविंग के दौरान मामूली गलती पर भी भारी जुर्माना लगेगा। चाहे ड्राइविंग के दौरान ओवरस्पीड का मामला हो, बिना हेल्मेट या बिना बेल्ट या फिर नशे में ड्राइविंग कर रहे हैं तो जुर्माने की रकम कई गुना तक बढ़ाने की तैयारी है। नए नियम के तहत दोपहिया वाहनों में ओवरलोडिंग पर पहले के 100 रुपये के मुकाबले अब 30 गुना यानी 3 हजार रुपये फाइन देना होगा। कुछ मामलों में बाकायदा सजा का प्रावधान तक है। कुछ मामलों में सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने तक का प्रावधान रखा है। किसी किशोर के ड्राइविंग दौरान सड़क पर कोई अपराध या हादसा होने पर गाड़ी मालिक या अभिभावक को दोषी माना जाएगा। उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा।

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गाड़ियों की खरीद की स्थिति में उसके रजिस्ट्रेशन का काम डीलर को देने से राज्यों को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि राजस्व का पैसा सीधा राज्य सरकारों के खाते में जाएगा। इतना ही नहीं, इस संबंध में राजस्व की दर का निर्धारण भी राज्य अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिल में 'मोटर वाहन दुर्घटना फंड' के गठन की बात कही गई है, जो भारत में सड़क का इस्तेमाल करने वालों को अनिवार्य बीमा कवर देगा।

हिट ऐंड रन पर सरकार देगी दो लाख मुआवजा

हिट ऐंड रन के मामले में मृतक के परिजनों को सरकार की ओर से दो लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी। फिलहाल महज 25,000 रुपये का ही प्रावधान है।

सभी रोड यूजर्स का इंश्योरेंस

मोटर वीइकल्स ऐक्सिडेंट फंड बनेगा, जो देश के सभी रोड यूजर्स को इंश्योरेंस कवर प्रदान करेगा। इसके तहत कुछ निश्चित तरह के हादसों को कवर किया जाएगा।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर देनदारी की सीमा खत्म

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर देनदारी की सीमा को समाप्त किया जाएगा। इससे पहले 2016 में तैयार प्रस्ताव में मौत पर 10 लाख और गंभीर घायल पर 5 लाख रुपये का प्रावधान था।

नाबालिग की गलती पर पैरंट्स होंगे जिम्मेदार

यदि किसी नाबालिग के द्वारा ट्रैफिक

नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके पैरंट्स को जिम्मेदार माना जाएगा। परिजनों को बचने के लिए यह साबित करना होगा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी या फिर उन्होंने ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया था। नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के तहत केस चलेगा। वीइकल्स का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है।

शराब पीना पड़ेगा भारी, अब 10,000 फाइन

नशे में गाड़ी चलाने पर न्यूनतम जुर्माने को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर दिया गया है। रैश ड्राइविंग पर फाइन भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के फाइन पर 5,000 रुपये तक का फाइन देना होगा, फिलहाल यह 500 रुपये है।

सीट बेल्ट और ओवर स्पीड पर भी बढ़ा फाइन

बिना सीट बेल्ट पहने चलाने पर 100 रुपये की बजाय 1,000 देना होगा। इसके अलावा तय सीमा से अधिक स्पीड से चलाने पर 400 के स्थान पर 1,000 से 2,000 रुपये तक फाइन देना होगा।

मोबाइल पर बात करने पर 5,000 फाइन

मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये तक फाइन देना होगा। फिलहाल यह महज 1,000 रुपये है।

अब राज्यसभा में जाएगा बिल

बहरहाल, लोकसभा के बाद यह बिल अब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद यह देश में कानून की शक्ल अख्तियार करेगा। सदन ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज कर दिया।

'निचले सदन में बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया कि सरकार का मोटर यान संशोधन बिल के जरिए राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। इसके प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है। केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था में बदलाव लाने और हादसों को कम करने की है।'

-नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री

आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़कर 31 अगस्त हुई

नयी दिल्ली । आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया। इस कदम से करदाताओं को राहत मिलेगी। इससे पहले वेतनभोगी करदाताओं और इकाइयों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा , ' केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया है। ' वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्त्रोत से कर कटौती (टीडीएस) का प्रमाणपत्र यानी फार्म 16 के देर से जारी होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के लिये फार्म -16 जारी करने की अंतिम तिथि 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया था। इसकी वजह से वेतनभोगी करदाताओं के पास 20 दिन के अंदर आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय बचा था।

बेंगलोर हवाईअड्डे ने विस्तार की उड़ान के साथ शुरू की 'डिजी यात्रा' सेवा

बेंगलुरू। एजेंसी

बेंगलोर हवाईअड्डे ने मंगलवार को विस्तार की एक उड़ान के साथ ' डिजी यात्रा ' सेवा शुरू कर दी। इसका उद्देश्य हवाईअड्डे पर यात्रियों को जगह - जगह दस्तावेज दिखाने के झंझट से मुक्त कराना है। बेंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (बीआईएएल) ने विज्ञप्ति में कहा कि वह धीरे - धीरे अन्य उड़ानों और एयरलाइन कंपनियों के लिए बायोमेट्रिक आधारित विमान में चढ़ने (बोर्डिंग) के समाधान मुहैया कराएगी। बेंगलोर हवाई अड्डे पर विस्तार की सभी उड़ानों के अक्टूबर तक बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रक्रिया में शामिल होने की उम्मीद है। डिजी यात्रा , नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की पहल है। इस सुविधा का उद्देश्य डिजिटल प्रणाली या ई - बोर्डिंग प्रक्रिया के तहत हवाईअड्डे में प्रवेश के लिए कागजी कार्रवाई को कम करना और बोर्डिंग के लिए यात्रियों के आधार नंबर और मोबाइल फोन जैसे दस्तावेज का उपयोग सुनिश्चित करना है। बीआईएएल ने कहा , ' कैम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 22 जून को पंजीकरण से बोर्डिंग तक की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बायोमेट्रिक - आधारित स्व - बोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की गई है।

डिजिटल बोर्डिंग प्रक्रिया के तहत यात्री टर्मिनल पहुंचने से पहले अपना पहचान पत्र (आईडी) और बायोमेट्रिक आंकड़ों को दर्ज करके इन्हें अपने उड़ान से जुड़े विवरण से जोड़ सकते हैं। इसके बाद जब वह यात्रा के लिए हवाईअड्डे पर पहुंचेंगे तो उन्हें यात्रा से जुड़े दस्तावेजों को अपने साथ लाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल वे बायोमेट्रिक तकनीक द्वारा हर जांच बिंदु (टचप्वाइंट) पर प्रमाणित और सत्यापित हो जाएंगे। बीआईएएल ने कहा कि यह प्रक्रिया उच्च स्तर की सुरक्षा की पेशकश करने के साथ गोपनीयता के कड़े मानकों का भी ध्यान रखती है। बोर्डिंग प्रक्रिया के लिए बायोमैट्रिक आंकड़ों का उपयोग सिर्फ यात्रियों के सत्यापन के लिए किया जाएगा न कि उनकी पहचान के लिए। इसके अलावा उड़ान पूरी होने के कुछ घंटों के अंदर यात्रियों के आंकड़ों को मिटा दिया जाएगा। फिलहाल यह सुविधा बेंगलुरू से मुंबई जाने वाली विस्तार की उड़ान यूके - 864 के यात्रियों को मिलेगी। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें हर जगह पर यात्रा से जुड़े दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी।

साइबर क्राइम से भारतीय कंपनियों को औसतन 13 करोड़ का नुकसान : IBM

नई दिल्ली। एजेंसी

सूचनाओं में सेंध लगने से देश में कंपनियों को जुलाई 2018 से अप्रैल 2019 के बीच औसतन 12.80 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी आईबीएम द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर यह औसत करीब 27.03 करोड़ रुपये है। सेंध लगाने की इन घटनाओं में औसतन 25,575 रिकॉर्ड प्रभावित हुए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में सूचनाओं में सेंध लगाये जाने अथवा डेटा चोरी से प्रति व्यक्ति नुकसान 5,019 रुपये है जबकि वैश्विक औसत 150 डॉलर का है। भारत में इन घटनाओं में औसतन 35,636 रेकॉर्ड प्रभावित होते हैं। यह रिपोर्ट पोनेमोन इंस्टीट्यूट ने तैयार की है और आईबीएम सिक्यॉरिटी ने इसे प्रायोजित किया है। आईबीएम इंडिया/साउथ एशिया के सिक्यॉरिटी सॉफ्टवेयर लीडर वैद्यनाथन अय्यर ने कहा, 'भारत में तेजी से साइबर अपराध में बदलाव हो रहा है। यह अब बेहद संगठित है और तालमेल पर आधारित है। डेटा चोरी से नुकसान में लगातार वृद्धि हो रही है।' उन्होंने कहा कि जब साइबर सुरक्षा की बात आती है तो कंपनियों को तीन मूल क्षेत्रों में खासतौर से निवेश करने की जरूरत है। इनमें व्यावसायिक उद्देश्य के आधार पर जोखिम का आकलन करना, डिजिटल विश्वास सुनिश्चित करना और ज्ञानात्मक जोखिम प्रबंधन पर गौर किया जाना जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत डेटा चोरी अथवा सेंध लगने के पीछे प्रमुख वजह जो रही हैं उनमें आपराधिक हमले होना 51 प्रतिशत, प्रणालीगत समस्या की वजह से 27 प्रतिशत और मानव गलती के कारण 22 प्रतिशत डेटा चोरी अथवा सूचनाएं लीक होती हैं।

पानी की प्लास्टिक बोतलों से रेलवे बना रही टी-शर्ट, खाली बोतल देने पर मिलेंगे 5 रुपये

नई दिल्ली। एजेंसी

रेलवे स्टेशनों और ट्रेन के डिब्बों में खाली पड़ी प्लास्टिक की बोतलें अब जल्द ही कल की बात होगी, क्योंकि रेलवे, पानी की इन खाली प्लास्टिक की बोतलों से टी-शर्ट और टोपी बना रहा है। इसके लिए बोतलों को इकट्ठा करने का रेलवे ने नायाब तरीका भी खोज निकाला है। प्लास्टिक की बोतल को जमा करने वाले को प्रति बोतल के लिए पांच रुपये दिए जाएंगे। इस कदम से पर्यावरण को संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के चार स्टेशनों पटना जंक्शन, राजेंद्रनगर, पटना साहिब और दानापुर स्टेशन पर रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई है, जिसमें पानी की प्लास्टिक की बोतलों को क्रश कर इससे टी-शर्ट और टोपी बनाई जा रही है।

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) राजेश कुमार ने आईएएनएस से कहा, 'रेलवे स्टेशनों पर बेकार पड़े रहने वाली खाली पानी की

प्लास्टिक बोतलों से पूर्व मध्य रेलवे अब टी-शर्ट बना रही है। रेलवे स्टेशनों पर लगे बोतल क्रशर मशीन के प्लास्टिक का इस्तेमाल टी-शर्ट बनाने के लिए होगा.' उन्होंने कहा, 'ये टी-शर्ट सभी मौसम में पहनने लायक होंगी। टी-शर्ट बनाने के लिए रेलवे का मुंबई की एक कंपनी से करार हुआ है। जल्द ही इन प्लास्टिक की बोतलों से बना टी-शर्ट बाजार में लोगों के लिए उपलब्ध होगा।

उन्होंन कहा कि अभी हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची में ऐसी ही टी-शर्टों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। उन्होंने बताया कि इससे स्टेशनों और पटरियों पर छोड़े गए प्लास्टिक कचरे व प्रदूषण से रेलवे को मुक्ति मिलेगी. उन्होंने कहा, 'एक अनुमान के मुताबिक भारत विश्व में उपभोग होने वाले प्लास्टिक का दो से तीन प्रतशत उपभोग करता है। प्रति व्यक्ति प्रति दिन प्लास्टिक औसत खपत सात किलोग्राम से आठ किलोग्राम है. अकेले रेलवे में पानी की बोतल के कुल कचरे का पांच प्रतिशत इसमें योगदान होता है।

उन्होंने कहा पानी की प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करने के बाद इसे क्रश कर देना होता है, परंतु अज्ञानता के कारण लोग ऐसा नहीं करते और इसे कहीं भी फेंक देते हैं, इससे रेलवे स्टेशनों और रेलवे पटरियों पर प्रदूषण फैलता है। उन्होंने कहा, 'अब यात्रियों को खाली बोतल के लिए पांच रुपये मिलेंगे. यह पांच रुपये उन्हें वाउचर के रूप में रेलवे की एजेंसी बायो-क्रश की ओर से मिलेंगे. इस पैसे का इस्तेमाल कई चुनिंदा दुकानों और मॉल में सामान खरीदने के लिए किया जा सकेगा।

सीपीआरओ कुमार ने कहा कि यात्री को अपनी खाली बोतलों को पटना जंक्शन, राजेंद्रनगर, पटना साहिब और दानापुर स्टेशन पर लगी बोतल क्रशर मशीन में डालना होगा. क्रशर मशीन में बोतल डालने के समय मोबाइल नंबर डालना पड़ता है. उसके बाद बोतल डालने और तत्पश्चात क्रश होने पर थैंक्यू मैसेज के साथ राशि से संबंधित वाउचर मिल जाता है. रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि बोतलों को क्रश कर इसका लिक्विड बनता है उसके बाद टी-शर्ट, टोपी बनाई जाती है. उन्होंने कहा कि इससे पेंट भी बन सकता है.

18 राज्यों ने प्लास्टिक थैलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगायाः CPCB

नई दिल्ली। एजेंसी

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बताया है कि 18 राज्य प्लास्टिक थैलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुके हैं और पांच राज्यों ने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इन पर आंशिक रूप से रोक लगा रखी है। बोर्ड ने एनजीटी को यह भी बताया कि 12 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लेकर कार्य योजना पेश कर चुके हैं। बोर्ड ने एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ को बताया,राज्य प्लास्टिक के थैलों/उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसके अलावा पांच राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल ने धार्मिक/ऐतिहासिक स्थानों पर

प्लास्टिक के थैलों/उत्पादों पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। बोर्ड ने यह भी कहा कि सात राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों असम, बिहार, गोवा, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी और तेलंगाना ने प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है जबकि ओडिशा ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। एनजीटी ने बोर्ड को 30 सितंबर तक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने और संबंधित राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आगे कार्रवाई करने के लिए कहने का निर्देश दिया। एनजीटी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन तथा इससे संबंधित मामलों पर दायर सीपीसीबी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

अनुसंधान विकास पर व्यय 2022 तक जीडीपी का 2 प्रतिशत होः पीएमईएसी

नयी दिल्ली। देश में अनुसंधान एवं विकास मद में व्यय आर्थिक वृद्धि के अनुरूप होना चाहिए और 2022 तक इसको सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के कम-से-कम 2 प्रतिशत पर पहुंचने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने यह राय व्यक्त की है। 'आर एंड डी व्यय परिवेश' शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार पीएमईएसी ने कहा है कि केंद्र में संबंधित मंत्रालयों के लिए अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार प्रौद्योगिकी के विकास तथा उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने लेकर अपने बजट का एक निश्चित हिस्सा अनुसंधान एवं नवोन्मेष की योजनाओं के लिए रखना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अनुसंधान एवं विकास पर पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.6 से 0.7 प्रतिशत के बीच टिका हुआ है। इसके विपरीत यह अमेरिका (2.8 प्रतिश्त), चीन (2.1 प्रतिशत), इस्राइल (4.3 प्रतिशत) और दक्षिण कोरिया (4.2 प्रतिशत) है। पीएमईएसी के मुताबिक, "भारत को नवप्रवर्तन एवं औद्योगिक अनुसंधान और विकास में अगुवा बनने के लिये इस मद में निजी क्षेत्र का व्यय भी बढ़ाना होगा। यह इस समय जीडीपी के मात्र 0.35 प्रतिशत के स्तर पर है। इसके लिये यह भी जरूरी है कि देश में पंजीकृत मझोले और बड़े उद्यम भी अपनी आय का कुछ हिस्सा शोध एवं विकास पर खर्च करें। " समिति का सुझाव है कि विनिर्माण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में निवेश के लिये प्रोत्साहित करने के लिए इस मद में किए गए व्यय पर भारांकित कटौती को एक अप्रैल 2020 के बाद भी जारी रखी जाएगा।

आयकर कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत आंतरिक स्तर पर आर एंड डी सुविधाओं पर किए गए निवेश के 150 प्रतिशत के बराबर कटौती का लाभ मिलत है। र अप्रैल 2020 से भारांकित कटौती की जगह केवल निवेश के बराबर यानी निवेश के 100ज़ के बराबर ही आय-कटौती का लाभ मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से वित्त पोषण करें तो अच्छा होगा। यह कार्य केंद्र प्रोयोजित योजनाओं के माध्यम से हो सकता है। मौजूदा कर कानून सीएसआर (कंपनी सामाजिक जिम्मेदारी) के तहत आर एंड डी (अनुसंधान एवं विकास) में निवेश का समर्थन करता है। लेकिन इसमें आर एंड डी गतिविधियों के प्रकार का दायरा बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में 30 अनुसंधान एवं विकास निर्यात केंद्र सृजित करने और बड़ी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये 5,000 करोड़ रुपये के कोष की वकालत की गयी है।

इस शिवालय में पढ़ी जाती है 'नमाज'

श्रावण विशेष

इस्लाम में मूर्ति पूजा निषेध मानी गई है। इसलिए आमतौर पर मुसलमान मंदिर या मूर्ति पूजा किए जानेवाले दूसरे धर्म स्थलों से दूर ही रहते हैं। मुसलमानों एवं गैर इस्लामिक लोगों के बीच अक्सर इसी वजह से विवाद होता रहता है लेकिन हिंदुस्थान में एक शिवालय इसका अपवाद है। इस शिव मंदिर में हिंदू, भगवान शिव का जल से अभिषेक करते ही हैं परंतु मुस्लिम लोग भी बेझिझक होकर नमाज अदा करते हैं। इस मंदिर का नाम झारखंडी महादेव है। यह मंदिर बहुत ही खास और अनोखा है। उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले से कुछ दूरी पर सरया तिवारी नाम का एक गांव है। इस गांव में शिवजी का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में जहां हिंदू पूजा करते हैं, वहीं मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते हैं।

इसलिए शिव मंदिर में पढ़ते हैं नमाज

सामाजिक समरसता की मिसाल बनें इस मंदिर में मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़ने के पीछे की कहानी विदेशी मुस्लिम हमलावर महमूद गजनवी से जुड़ी है। कहानी के अनुसार, इस शिवलिंग की महिमा और प्रसिद्ध सुनने पर मेहमूद गजनवी ने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की। अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी वह इसे तोड़ नहीं पाया। शिवलिंग को न तोड़ पाने पर उसने इस पर कुरान का एक कलमा लिखवा दिया, ताकि इस शिवलिंग की प्रसिद्धि कम हो जाए और हिंदू इसकी पूजा करना बंद कर दे। मेहमूद के कलमा लिखवाने के बाद इस शिवलिंग की प्रसिद्धि कई गुना बढ़ गई और यह शिव मंदिर हिंदुओं के साथ-साथ मुस्लिमों की भी आस्था का केंद्र बन गया।

भोलेनाथ को प्रिय है भस्म

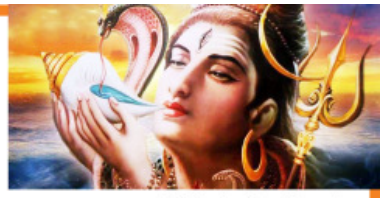

भगवान भोलेनाथ का स्वरूप जिस तरह से अजीबोगरीब है उसी तरह उनकी पसंद भी अजीबोगरीब ही है। उन्हें विचित्र सामग्री ही प्रिय लगती है। फिर चाहे वह जहरीला धतूरा, नशीली भांग, गले में लिपटे सर्पों की माला, गणों में भूत-प्रेत, पिशाच निशाचर के साथ-साथ वे अपने तन पर भस्म रमाए रहते हैं। भगवान शिव का ऐसा अनोखा रूप और उनके शरीर पर लिपटी सौंधी भस्म लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करती है।

एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपने तन पर जो भस्म रमाई है, वह उनकी पत्नी सती की चिता की भस्म थी, जो कि अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत हो वहां हो रहे यज्ञ के हवनकुंड में कूद गई थी। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वे बहुत बेचैन हो गए। जलते कुंड से सती के शरीर को निकालकर प्रलाप करते हुए ब्रह्माण्ड में तांडव नृत्य करने लगे। उनके क्रोध व बेचैनी से सृष्टि खतरे में पड़ गई, जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शव के टुकड़े-टकड़े कर दिए थे। तब जहां-जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हो गई

लेकिन पुराणों के अनुसार जलते अग्नि कुंड में सती के आत्मदाह के बाद शिव का संताप खत्म ही नहीं हो रहा था। तब श्री हरि ने सती के शरीर को भस्म में परिवर्तित कर दिया। शिव ने विरह की अग्नि में भस्म को ही सती की अंतिम निशानी के तौर पर तन पर लगा लिया। भगवान शिव के तन पर भस्म रमाने का एक रहस्य यह भी है कि राख विरक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव चूंकि बहुत ही लौकिक देव लगते हैं। कथाओं के माध्यम से उनका रहन-सहन एक आम संन्यासी सा लगता है। एक ऐसे ऋषि सा, जो गृहस्थी का पालन करते हुए मोह माया से विरक्त रहते हैं और संदेश देते हैं कि अंत काल सब कुछ राख हो जाना है।

एक रहस्य यह भी हो सकता है चूंकि भगवान शिव को विनाशक भी माना जाता है। ब्रह्मा जहां सृष्टि की निर्माण करते हैं तो विष्णु पालन-पोषण लेकिन जब सृष्टि में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो भगवान शिव विध्वंस कर डालते हैं।

विध्वंस यानि की समाप्ति और भस्म इसी अंत इसी विध्वंस की प्रतीक भी है। शिव हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि पाप के रास्ते पर चलना छोड़ दें अन्यथा अंत में सब राख ही होगा।

शिव का शरीर पर भस्म लपेटने का दार्शनिक अर्थ यही है कि यह शरीर जिस पर हम घमंड करते हैं, जिसकी सुविधा और रक्षा के लिए ना जाने क्या-क्या करते हैं, एक दिन इसी तरह भस्म के समान हो जाएगा। शरीर क्षणभंगुर है और आत्मा अनंत। कई संन्यासी तथा नागा साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म उनके शरीर की कीटाणुओं से तो रक्षा करता ही है तथा सब रोम कूपों को ढंककर ठंड और गर्मी से भी राहत दिलाती है।

रोम कूपों के ढंक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती इससे शीत का अहसास नहीं होता और गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं होती। इससे गर्मी से रक्षा होती है। मच्छर, खटमल आदि जीव भी भस्म रमे शरीर से दूर रहते हैं।

चमत्कारी है महाकाल की भस्मार्ती

उज्जैन स्थित महाकालेश्वर की भस्मार्ती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि वर्षों पहले श्मशान भस्म से भूतभावन भगवान महाकाल की भस्म आरती होती थी लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो चुकी है और अब कंडे की भस्म से आरती-श्रृंगार किया जा रहा है। वर्तमान में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने औषधियुक्त उपलों में शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाई भस्म का प्रयोग किया जाता है।

जलते कंडे में जड़ीबूटी और कपूर-गुगल की मात्रा इतनी डाली जाती है कि यह भस्म ना सिर्फ सेहत की दृष्टि से उपयुक्त होती है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हो जाती है। श्रौत, स्मार्त और लौकिक ऐसे तीन प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ किया हो वह भस्म श्रौत है, स्मृति की विधि से यज्ञ किया हो वह स्मार्त भस्म है तथा कंडे को जलाकर भस्म तैयार की हो वह लौकिक भस्म है।

श्रावण मास का वैज्ञानिक कारण जानकर हैरान रह जाएंगे आप

श्रावण माह के बारे में मन में प्रश्न उपजते हैं।क्यों उपवास करते हैं? क्यों सभी शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं? क्यों जल चढ़ाते हैं? रुद्राभिषेक क्यों करते हैं? आध्यात्मिक संतों द्वारा अलग-अलग तरीके से समझाया जाता रहा है। विज्ञान, अध्यात्म एवं प्रायोगिक भाषा में इसे कुछ इस तरह समझा जा सकता है...

श्रावण मास क्यों मनाते हैं

श्रावण मास प्रकृति से आज तक जो भी हमने हवा, हरियाली, जल आदि जो निशुल्क उपयोग किया है, इसकी कृतज्ञता प्रकट करने का माह है श्रावण मास।

वैज्ञानिक कारण

वर्षों ऋतु का आगाज आषाढ़ माह से होने से श्रावण मास में उपजने वाला पत्ते और सब्जियां प्रथम वर्षा के जल से दूषित हो जाते हैं। हमारे ऋषियों ने इसको पहले ही जान लिया था। इसलिए पत्ते वाली सभी सब्जियां खाना वर्जित किया। इसलिए पूरे माह व्रत रखने का संदेश दिया गया, जो आज भी एक बड़ा वर्ग मानता है।

क्यों चढ़ाते शिवलिंग पर दूध : चूंकि प्रथम वर्षा ऋतु में उपजी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियों का सेवन गाय-भैंस के करने से निकलने वाला दूध भी दूषित होता है। अतः ऋषियों ने विष पीने वाले शिव पर सिर्फ श्रावण मास में दूध चढ़ाने का आदेश दिया।

पंचामृत क्या है

5 तत्व- दूध, दही, घी, शहद और शकर क्रमशः जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती तत्व का प्रति?निधित्व करते हैं, जिनसे मानव शरीर बना है। वह तत्व रूपी पंचामृत देकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं।

नाभि पर ब्रह्मा, छाती के मध्य भाग को विष्णु, मस्तक का मध्य भाग शिवजी का प्रतिनिधित्व करता है।

मुझको कहां ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास... की भावना के साथ श्रावण माह प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होकर मनाएं।

भगवान शिव के इन 10 प्रमुख नामों का अर्थ जानकर अचरज होगा आपको

भगवान शिव के कई नाम हैं जैसे शिव, शंकर, शम्भु, नीलकंठ, गंगाधर, त्रिशूलधारी, मृत्युंजय, पशुपति, पंचवक्त्र, शितिकंठ, खंडपरशु, प्रमथाधिव, रुद्र, आदिगुरु, महादेव, विष्णुवल्लभ, महाकाल, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ, परमात्मा, कपाली, भैरव आदि कहा जाता है। लेकिन हम बताएंगे यहां 10 प्रमुख नामों का अर्थ।

1.परमेश्वर- सर्वोच्च ईश्वर। 2.सर्वेश्वर- सभी का ईश्वर। 3.जगदिश्वर या विश्वेश्वर- जगत या सारे विश्व का ईश्वर। 4.महेश्वर- सबसे महान ईश्वर या माया के अधीश्वर। 5.योगेश्वर- योग का ईश्वर। 6.आदिश्वर- सबसे पहला ईश्वर। 7.त्रिलोकेश्वर- तीनों लोक का ईश्वर। 8.अनीश्वर- जो स्वयं ही सबके स्वामी है। 9.अर्धनारीश्वर- आधे नर और आधी नारी के रूप में पूर्ण ईश्वर। 10.शिव- वह जो नहीं है और वह जो शुभ है।

मॉनसून की सुस्त चाल से सोयाबीन रकबे में 10 प्रतिशत गिरावट का अनुमान

इंदौर। एजेंसी

प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में मॉनसून की धीमी चाल के बीच, केंद्र सरकार के एक संस्थान ने बुधवार को संशोधित अनुमान जताया कि देश में इस तिलहन फसल का रकबा 10 प्रतिशत गिरकर तकरीबन 100 लाख हेक्टेयर रह सकता है। इंदौर के भारतीय सोयाबीन अनुसन्धान संस्थान (आईआईएसआर) के निदेशक वीएस भाटिया ने को बताया, 'मौजूदा हालात के मद्देनजर हमें लगता है कि देश में खरीफ के इस मौसम के दौरान सोयाबीन का रकबा 100 लाख हेक्टेयर के आस-पास रह सकता है।' गौरतलब है कि आईआईएसआर निदेशक ने सात जुलाई को अपने पिछले अनुमान में कहा था कि मौजूदा खरीफ सत्र में सोयाबीन का राष्ट्रीय रकबा 110 लाख हेक्टेयर रह सकता है। वर्ष 2018 के खरीफ सत्र में भी देश में लगभग इतने ही क्षेत्र में सोयाबीन बोया गया था। बहरहाल, मॉनसून की सुस्त चाल के कारण आईआईएसआर निदेशक को अपना पिछला अनुमान संशोधित करना पड़ा है।

भाटिया ने बताया, 'सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक मध्यप्रदेश में मॉनसून पहले तो देरी से आया। इसके बाद सूबे में सोयाबीन की खेती वाले प्रमुख इलाकों में मॉनसूनी बारिश में कमी दर्ज की गयी। इसका सीधा असर सोयाबीन बुआई पर पड़ा है।' सोयाबीन फसल की मौजूदा स्थिति के बारे पूछे जाने पर उन्होंने बताया, 'मध्यप्रदेश के कुछ सोयाबीन उत्पादक हिस्सों में हालांकि पिछले दो दिन में मॉनसूनी बारिश का दौर फिर शुरू हुआ है। लेकिन सूबे के कई हिस्सों में वर्षा की लम्बी खेंच से किसान चिंतित हैं। इन इलाकों में अगर जल्द ही अच्छी बारिश नहीं हुई, तो सोयाबीन फसल की पैदावार पर असर पड़ सकता है।'

सरकार ने 2019-20 में चीनी का 40 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी दी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 40 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी दी। चीनी के बंपर उत्पादन के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 2019-20 के विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 275 रुपये प्रति क्विंटल पर कायम रखने का फैसला किया गया है। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जो मिलों को गन्ना खरीद के लिए किसानों को देना होता है। राज्य सरकारें इसके ऊपर गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य भी घोषित कर सकती हैं। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बुधवार को यहां हुई बैठक में खाद्य मंत्रालय के चीनी का 40 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी दी

गई। अगस्त, 2018 में केंद्र ने चीनी का 30 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया था जिससे सरकार पर 1,175 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था। यह कदम चीनी मिलों की नकदी की स्थिति सुधारने, गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान में मदद और घरेलू स्तर पर चीनी कीमतों को स्थिर करने के लिए उठाया गया था। देश का चीनी उत्पादन 2018-19 के विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान 3.29 करोड़ टन रहने का अनुमान है। चीनी की घरेलू मांग 2.6 करोड़ टन रहने की संभावना है। चीनी उद्योग के संगठन इस्मा के अनुसार, एक अक्टूबर, 2019 को नया चीनी सत्र शुरू होने के समय पुरानी चीनी का भंडार अपने सर्वकालिक उच्चस्तर 1.45 करोड़ टन पर रहने की उम्मीद है। सामान्य तौर पर उस समय 50 लाख टन के स्टाक की जरूरत होती है।

अमूल बाजार में उतारेगी ऊंटनी के दूध की 200 मिली की बोतल

वडोदरा। दुग्ध उत्पाद बनाने वाली प्रमुख कंपनी अमूल के प्रबंध निदेशक आर. एस. सोढ़ी ने कहा कि कंपनी ने एक सप्ताह के भीतर देश में पहली बार 200 मिली लीटर की बोतल में ऊंटनी का दूध पेश करने का फैसला किया है। सोढ़ी ने एजेंसी से बात करते हुए कहा कि 200 मिलीलीटर ऊंटनी के दूध वाली इस बोतल की कीमत 25 रुपये प्रति बोतल होगी। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण गांधीनगर में अमूल डेयरी के अत्याधुनिक विनिर्माण संयंत्र में किया जा रहा है। सोढ़ी ने कहा कि इससे पहले इस साल के आरंभ यानी जनवरी में अमूल ने ऊंटनी के दूध को 500 मिलीलीटर के बोतल में बाजार में उतारा था। इसके प्रत्येक बोतल की कीमत 50 रुपये थी।

श्रीलंका ने फिर शुरू की आगमन पर मुफ्त वीजा सेवा

अब भारत, चीन के पर्यटकों को भी मिलेगा लाभ

कोलंबो। एजेंसी

श्रीलंका ने देश के पर्यटन क्षेत्र को फिर पटरी पर लाने के लिए आगमन पर मुफ्त वीजा सेवा को फिर शुरू करने की घोषणा की। यह सेवा एक अगस्त से प्रभावी होगी। इस बार इस सेवा का लाभ भारत और चीन के पर्यटकों को भी मिलेगा। अप्रैल में ईस्टर के दिन हुए आतंकवादी हमले के बाद चीन ने इस सेवा को रोक दिया था। उल्लेखनीय है कि 21 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में नौ आत्मघाती हमलावरों ने तीन चर्च और कई लक्जरी होटल पर हमले को अंजाम दिया था। इसमें 258 लोगों की मौत हो गयी थी। घटना के बाद श्रीलंका ने 39 देशों को दी जाने वाली आगमन पर मुफ्त वीजा सेवा को बंद कर दिया था। श्रीलंका ने बुधवार को जानकारी दी कि इस सेवा को फिर से शुरू किया गया है। यह एक अगस्त से प्रभावी होगी। समाचार पोर्टल श्रीलंका मिरर ने पर्यटन एवं ईसाई मामलों के मंत्री जॉन अमारातुंगे के हवाले से कहा है कि 39 देशों को दी जाने वाली इस सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। इस सेवा का विस्तार भारत और चीन के पर्यटकों तक किया गया है। पहले भारत और चीन के पर्यटकों को इस सेवा का लाभ नहीं मिलता था। थाईलैंड, यूरोपीय संघ के सदस्य देश, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और कंबोडिया के पर्यटकों के लिए यह सेवा पहले से उपलब्ध है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा

अगले वित्त वर्ष से आठ फीसद से अधिक रहेगी भारत की विकास दर

न्यूयॉर्क। एजेंसी

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 से देश की विकास दर आठ फीसद से अधिक रहेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि जीएसटी जैसे संरचनात्मक सुधारों के मनचाहे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कुमार यहां टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरम मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में होगी। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में आयोजित इंडिया इन्वेस्टमेंट सेमिनार में मुख्य वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में मोदी सरकार विकास दर को वर्तमान करीब सात फीसद से बढ़ाकर आठ फीसद से ऊपर ले जाएगी। इससे देश को पांच लाख करोड़ डॉलर (करीब 347 लाख करोड़ रुपये) की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा। एक साक्षात्कार में राजीव कुमार ने कहा कि निजी तौर पर मेरा मानना है कि 2020-21 से देश की विकास दर आठ फीसद से अधिक रहने वाली है। यह दर कई साल तक जारी रहेगी। बुनियाद रख दी गई है और जीएसटी व इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसे संरचनात्मक सुधारों के लागू होने के बाद परिवर्तन शुरू हो चुका है। इनके प्रभाव के लिए जितना वक्त लगना चाहिए, वह लग चुका है और अब उनके लाभ मिलने शुरू होंगे। हमारे पास दहाई अंकों की विकास दर हासिल करने की क्षमता है।

आठ फीसद से अधिक की विकास दर जरूरीः कांत

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने सोमवार को कहा कि 2024-25 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश को आठ फीसद से अधिक की विकास दर हासिल करना होगा। आइआइएलएम इंस्टीट्यूट फॉर हाइयर एडुकेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कांत ने कहा कि आर्थिक विकास को निजी क्षेत्र से गति मिलती है। इसलिए भारत को निजी क्षेत्र के निवेश के लिए उचित माहौल बनाना होगा। अभी हमारी विकास दर करीब सात फीसद है। अब इसे बढ़ाने की चुनौती है। 2024-25 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें साल-दर-साल आठ फीसद से अधिक की दर से विकास करना होगा।

जॉर्जिया का वीएफएस ग्लोबल के साथ समझौता

नयी दिल्ली। पर्यटन और व्यवसाय के लिए जॉर्जिया की यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों को आसान पहुंच उपलब्ध कराने के इरादे से वीएफएस ग्लोबल और जॉर्जिया के विदेश मंत्रालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वीएफएस ग्लोबल ने सोमवार को यह जानकारी दी। जॉर्जिया के विदेश मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के निदेशक जियोर्जी तबातादजे ने कहा, 'यह समझौता भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए है। इस अनुबंध के अनुसार, वीएफएस ग्लोबल भारत भर में 16 जॉर्जिया वीज़ा आवेदन केंद्रों का संचालन करेगी।''

सभी कंपनियों को मिल सकता है 25% कॉर्पोरेट टैक्स का फायदा

●मोदी सरकार के 2014 के पहले बजट में कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25 पर्सेंट करने का वादा किया गया था ●बजट में 400 करोड़ तक की सालाना आमदनी वाली कंपनियों के लिए टैक्स 30 से घटाकर 25ञ किया गया ●अब सिर्फ 0.7 पर्सेंट कंपनियां बची रह गई हैं, जिन्हें ऊंची दरों पर टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 25 पर्सेंट करने का संकेत दिया है। 5 जुलाई के बजट में उन्होंने 400 करोड़ रुपये तक की आमदनी वाली कंपनियों को 25 पर्सेंट के कम टैक्स का फायदा देने का प्रस्ताव रखा था। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में मंगलवार को वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, 'हम 99.3 पर्सेंट कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 25 पर्सेंट कर चुके हैं। कुछ ही कंपनियां इससे अधिक टैक्स दे रही हैं और उन्हें भी जल्द ही इस दायरे में लाया जा सकता है।'

निर्मला ने कहा कि मोदी सरकार के 2014 के पहले बजट में कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25 पर्सेंट करने का वादा किया गया था और इसे पूरा किया गया है। वित्त विधेयक को राज्यसभा ने मंगलवार को ध्वनिमत से पारित करके लोकसभा को वापस लौटा दिया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट के पास होने की प्रक्रिया पूरी हो गई।

वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि सरकार ने टैक्स पर जो प्रस्ताव रखे हैं, उनका मकसद संपत्ति का पुनर्वितरण है ताकि समावेशी विकास हो सके। उन्होंने बजट भाषण में 400 करोड़ रुपये तक की सालाना वाली आमदनी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 30 पर्सेंट से घटाकर 25 पर्सेंट करने का प्रस्ताव रखा था। निर्मला ने बजट में कहा था, 'जहां तक कॉर्पोरेट टैक्स का सवाल है, हम इसमें सिलसिलेवार कटौती जारी रखेंगे। अभी 250 करोड़ तक की आमदनी वाली कंपनियों पर 25 पर्सेंट का टैक्स लगता है। मैं इसके दायरे में 400 करोड़ रुपये तक की आमदनी वाली कंपनियों को लाने का प्रस्ताव पेश कर रही हूं।' इसके बाद सिर्फ 0.7 पर्सेंट कंपनियां बची रह जाएंगी, जिन्हें ऊंची दरों पर टैक्स का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार और बड़े जनादेश के साथ सत्ता में लौटी है। सरकार नया भारत बनाना चाहती है, जिसमें अधिक पारदर्शिता हो। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस हो। उन्होंने कहा था कि हम संसाधनों के बंटवारे का तरीका बदलकर समाज में समानता बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की हालत सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। इस सेक्टर में कैश की कमी दूर करने की कोशिश की जा रही है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल पर सेस बढ़ाने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अभी महंगाई दर काफी कम है। इसलिए सेस बढ़ाने से महंगाई का दबाव नहीं बढ़ेगा। साल में एक बैंक खाते से एक करोड़ से अधिक रकम निकालने पर 2 पर्सेंट के टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (टीडीएस) के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि यह कुल टैक्स देनदारी के अतिरिक्त नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसे टैक्स रिटर्न भरते समय कुल बकाया टैक्स से घटाया जा सकता है। इसे टैक्सपेयर की आमदनी नहीं माना जाएगा। यह नियम 1 सितंबर से लागू होगा।

Reliance
POLYMERS
Indore Depo :
131-132, Industrial Area,
Sector-D, Sanwer Road, Indore
Gwalior Depo :
C/o Bhagwati Cools Pvt.Ltd.
37-B, Maharajpura Industrial
Area, Gwalior
Raipur Depo :
C/o, Sun & Sun Cold Storage Pvt.Ltd.
Godown No.2, Industrial Area,
Bilaspur Road, Bhanpuri, Raipur

distribution redefined
AVJ POLYMER INDIA LLP
DEALER : RELIANCE INDUSTRIES LTD. FOR MP & CG
133, Industrial Area, Sector-D,
Sanwer Road, Indore (M.P.)
Ph: +91 731 2973343
Email : avjpolymer@gmail.com Website : www.avjpolymer.com
Vikas Bangard Mob- 9179161616
Vishal Soni Mob- 9826700343
Ashish Jain Mob- 9425044944
Rakesh Biyani Mob- 9109195565

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।